www.summerexpress.in

समर एक्सप्रेस

सूर्योदय सुबह 5:30 बजे
सूर्यास्त शाम 7:34 बजे

R.N.I NO. CHMUL/25/A1155

• साल-1 • अंक-302 • पृष्ठ-8 • मूल्य-5 रूपये • मंगलवार 7, जुलाई 2026 • चंडीगढ़ • पंजाब • हरियाणा • हिमाचल • ग्रुप एडिटर : अर्शदीप सिंह समर • एग्जीक्यूटिव एडिटर : नितिन उपमन्यु

न्यूज ब्रीफ

हाईकोर्ट को मिले दो नए स्थायी जज

चंडीगढ़| पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में सोमवार को जस्टिस हरमीत सिंह ग्रेवाल और जस्टिस दीपेंद्र नलवा ने स्थायी न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस शील नागू ने दोनों न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। केंद्र सरकार ने हाल ही में उनकी स्थायी नियुक्ति को मंजूरी दी थी। दोनों इससे पहले अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्यरत थे। इन नियुक्तियों के बाद भी हाईकोर्ट में न्यायाधीशों के कई पद रिक्त हैं और 10 अन्य अतिरिक्त न्यायाधीशों को स्थायी नियुक्ति मिलने का इंतजार है। न्यायिक कार्यों के बढ़ते बोझ को देखते हुए इन नियुक्तियों को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पीके बांकीपुर से लड़ेंगे विधानसभा उपचुनाव

पटना| बांकीपुर विधानसभा सीट पर जनसुराज पार्टी की ओर से प्रशांत किशोर उम्मीदवार होंगे। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने इसकी घोषणा की है। इस घोषणा के बाद से ट्विटर पर ट्रेंड होने लगा 'बिहार रिजेक्ट पीके'। वहीं, प्रशांत किशोर ने कहा कि चार सालों से जन सुराज ही मेरी जिंदगी है। पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है, उसे पूरा करने का प्रयास करूंगा। बांकीपुर से अगर जीत मिलती है तो उससे पार्टी का मनोबल काफी बढ़ेगा व पार्टी आगे बढ़ेगी। नितिन नबीन के राज्यसभा सदस्य बनने के बाद से ही पीके के बांकीपुर से चुनाव लड़ने की चर्चा थी। पीके ने कहा था- अगर मेरे चुनाव लड़ने से भाजपा बांकीपुर जैसी मजबूत सीट हारती है, तो मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूं।

जगन्नाथ रथयात्रा गलत समय पर न निकालें

भुवनेश्वर| पुरी के गजपति महाराज और श्रीजगन्नाथ मंदिर प्रबंधन समिति के अध्यक्ष दिब्यसिंह देब ने इस्कॉन प्रबंधन से अपील की है कि वह गलत समय पर रथयात्रा न निकाले। इस्कॉन यात्रा का आयोजन ऐसी तारीखों पर कर रहा है, जो शास्त्रों के अनुसार नहीं हैं। उन्होंने मायापुर में इस्कॉन की गवर्निंग बॉडी कमीशन के चेयरमैन के नाम लिखे पत्र में अलग-अलग समय पर रथ यात्रा निकालने पर आपत्ति जताई है। 21 जून को लंदन में, 14 जून को न्यूयॉर्क सिटी में और 5 जुलाई को सिडनी में रथयात्रा निकाली गई। इस साल, स्नान पूर्णिमा 29 जून को थी और मुख्य रथयात्रा 16 जुलाई को होगी। रथयात्रा हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हमेशा आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पर होती है।

पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की नेतृत्व क्षमता पर उठे सवाल

चुनाव से पहले कांग्रेस में बढ़ी कलह: चन्नी दिल्ली पहुंचे, बघेल की बैठक का बायकॉट

एक सांसद व छह विधायकों सहित कई नेताओं ने चन्नी के पक्ष में, वड़िंग बोले-पार्टी में कोई गुटबाजी नहीं

समर न्यूज | चंडीगढ़/नई दिल्ली

पंजाब विधानसभा चुनाव की तैयारियों के बीच कांग्रेस की अंदरूनी खींचतान अब खुलकर सामने आ गई है। पूर्व मुख्यमंत्री एवं जालंधर सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के समर्थकों ने पार्टी की हालिया संगठनात्मक नियुक्तियों पर असंतोष जताते हुए शक्ति प्रदर्शन किया।

चन्नी समर्थक नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल दिल्ली पहुंच गया है, जहां पार्टी हाईकमान से मुलाकात की कोशिश की गई। इस घटनाक्रम ने पंजाब कांग्रेस में नेतृत्व को लेकर चल रहे विवाद को और गहरा कर दिया। सूत्रों के अनुसार, कांग्रेस के पंजाब प्रभारी भूपेश बघेल द्वारा चंडीगढ़ में बुलाई गई बैठक का चन्नी समर्थक गुट के कई नेताओं ने बहिष्कार किया। दूसरी ओर, चन्नी के आवास पर हुई बैठक में एक सांसद और छह विधायकों सहित अनेक नेताओं ने हिस्सा लिया तथा प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के नेतृत्व पर सवाल उठाए।

कई नेताओं ने सार्वजनिक रूप से मांग की कि आगामी विधानसभा चुनाव चन्नी के नेतृत्व में लड़ा जाए। यह विवाद ऐसे समय सामने आया है जब कांग्रेस हाईकमान ने हाल ही में पंजाब संगठन में संतुलन बनाने की कोशिश की थी।

पार्टी ने अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग को प्रदेश अध्यक्ष और प्रताप सिंह बाजवा को विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर बरकरार रखा, जबकि चरणजीत सिंह चन्नी को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा और विजय इंदर सिंगला समेत अन्य वरिष्ठ नेताओं को भी अलग-अलग समितियों की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। उद्देश्य सभी प्रमुख गुटों को साथ लेकर चुनावी तैयारी करना था, लेकिन फैसले के कुछ ही दिनों बाद असंतोष खुलकर सामने आ गया।

पार्टी हाईकमान डैमेज कंट्रोल में जुटा

दिल्ली में कांग्रेस नेतृत्व डैमेज कंट्रोल में जुट गया है। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल पहले भी पंजाब के वरिष्ठ नेताओं के साथ कई दौर की बैठकें कर चुके हैं। हालिया घटनाक्रम के बाद प्रभारी भूपेश बघेल को एक बार फिर सक्रिय भूमिका में उतारा गया है ताकि चुनाव से पहले संगठनात्मक नुकसान को रोका जा सके।

चन्नी गुट ने कहा- संगठनात्मक नेतृत्व की समीक्षा जरूरी

चन्नी समर्थकों का तर्क है कि हाल के स्थानीय निकाय चुनावों और उपचुनावों के प्रदर्शन के आधार पर संगठनात्मक नेतृत्व की समीक्षा आवश्यक है। उनका कहना है कि राज्य में कांग्रेस को मजबूत विकल्प बनाने के लिए नेतृत्व में बदलाव पर गंभीरता से विचार होना चाहिए। हालांकि, पार्टी हाईकमान की ओर से अभी तक प्रदेश अध्यक्ष बदलने का कोई आधिकारिक संकेत नहीं दिया गया है।

फिलहाल नियुक्तियों में बदलाव की घोषणा नहीं

कांग्रेस के आधिकारिक सार्वजनिक बयानों में फिलहाल संगठनात्मक नियुक्तियों में किसी नए बदलाव की घोषणा नहीं की गई है। पार्टी नेतृत्व का जोर सभी वरिष्ठ नेताओं को साथ लेकर 2027 के विधानसभा चुनाव की रणनीति तैयार करने पर है। ऐसे में आने वाले दिनों में दिल्ली में होने वाली बैठकों और हाईकमान के फैसलों पर पंजाब कांग्रेस की आगे की दिशा काफी हद तक निर्भर करेगी।

वॉट्सएप यूजरनेम फीचर पर जवाब की समयसीमा 9 तक

ऑनलाइन फ्रॉड व 'डिजिटल अरेस्ट' का जताया खतरा

एजेंसी | नई दिल्ली

केंद्र सरकार ने वॉट्सएप के प्रस्तावित 'यूजरनेम' फीचर को लेकर मेटा (मेटा) को जवाब देने के लिए दी गई समयसीमा बढ़ाकर 9 जुलाई कर दी है। पहले कंपनी को 6 जुलाई तक अपना पक्ष रखना था। सरकार का कहना है कि इस फीचर के लागू होने से ऑनलाइन ठगी, फिशिंग, पहचान की नकल (इम्पर्सनेशन) और तथाकथित 'डिजिटल अरेस्ट' जैसे साइबर अपराधों का खतरा बढ़ सकता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इससे पहले मेटा को नोटिस जारी कर भारत में इस फीचर के रोलआउट पर फिलहाल रोक लगाने और इसकी कार्यप्रणाली से जुड़ा विस्तृत स्पष्टीकरण मांगा था। मंत्रालय का कहना है कि यूजरनेम के जरिए बिना मोबाइल नंबर साझा किए संपर्क करने की सुविधा साइबर अपराधियों के लिए फर्जी पहचान बनाकर लोगों को निशाना बनाना आसान कर सकती है। सरकार ने विशेष रूप से फिशिंग, सरकारी एजेंसियों या बैंकों के नाम से फर्जी अकाउंट बनाकर धोखाधड़ी व डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में वृद्धि की आशंका है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार ने मेटा को अतिरिक्त समय इसलिए दिया है ताकि कंपनी अपने सुरक्षा तंत्र और तकनीकी उपायों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत कर सके। मंत्रालय यह भी जानना चाहता है कि यूजरनेम के दुरुपयोग, फर्जी प्रोफाइल और पहचान की नकल को रोकने के लिए कौन-कौन से सुरक्षा प्रावधान लागू किए जाएंगे।

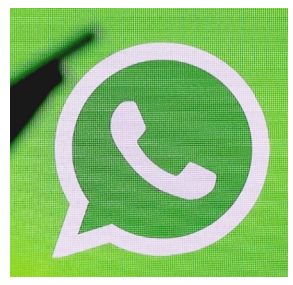

उपयोगकर्ताओं की निजता पर जोर...

वॉट्सएप का कहना है कि यूजरनेम फीचर को उपयोगकर्ताओं की निजता बढ़ाने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। कंपनी के अनुसार, अकाउंट बनाने के लिए मोबाइल नंबर की आवश्यकता बनी रहेगी और यूजरनेम से जुड़े कई सुरक्षा उपाय पहले से शामिल किए गए हैं। मेटा का दावा है कि प्रसिद्ध व्यक्तियों और संस्थानों की पहचान से जुड़े नामों के दुरुपयोग को रोकने के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था तैयार की गई है। डिजिटल अधिकारों से जुड़े कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि यह फीचर उपयोगकर्ताओं की गोपनीयता को मजबूत कर सकता है, जबकि सरकार का पक्ष है कि किसी भी नई डिजिटल सुविधा के लागू होने से पहले उसके संभावित सुरक्षा जोखिमों का मूल्यांकन आवश्यक है। फिलहाल यूजरनेम फीचर का भारत में व्यापक रोलआउट रुका हुआ है और अब सबकी नजर 9 जुलाई तक मेटा की ओर से दिए जाने वाले जवाब और सरकार के अगले फैसले पर टिकी है।

पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली, पंचकूला में बारिश जलभराव, 4 दिन और भारी बारिश के आसार

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाब, चंडीगढ़, मोहाली और पंचकूला के कई इलाकों में सोमवार को तेज बारिश हुई। कई निचले क्षेत्रों में जलभराव हो गया, जबकि कुछ स्थानों पर घरों और दुकानों में भी पानी घुसने की खबरें सामने आईं। बारिश के कारण प्रमुख सड़कों पर वाहनों की लंबी कतारें लगीं।

मोहाली, पंचकूला और चंडीगढ़ के कई सेक्टरों में जलनिकासी व्यवस्था पर दबाव दिखाई दिया। वहीं पंजाब के विभिन्न जिलों में भी रुक-रुककर हुई बारिश से मौसम सुहावना हो गया, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव की समस्या बनी रही। भारत मौसम विज्ञान विभाग के अनुसारअगले चार दिनों तक गरज-चमक, तेज हवाओं और भारी बारिश की संभावना बनी हुई है।

तीन दिन बारिश की चेतावनी

मौसम विशेषज्ञों ने लगातार तीन दिन बारिश की चेतावनी दी है कि लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, बिजली गिरने और तेज हवाओं जैसी स्थितियां बन सकती हैं। विभाग ने कई जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए लोगों को अनावश्यक यात्रा से बचने और जलभराव वाले क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी। विभाग का कहना है कि मानसूनी गतिविधियां 9-10 जुलाई तक सक्रिय रहने की संभावना है, जिससे कई स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। तापमान में भी उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है।

4 साल बाद अधिक अग्निवीरों को स्थायी सेवा में रखने की तैयारी : अग्निपथ की योजना में बदलाव पर मंथन

एजेंसी | नई दिल्ली

अग्निपथ योजना के तहत भर्ती हुए पहले बैच के अग्निवीरों का चार वर्षीय कार्यकाल इस वर्ष पूरा होने जा रहा है। ऐसे में तीनों सेनाओं ने मौजूदा व्यवस्था में बदलाव का प्रस्ताव तैयार किया है।

वर्तमान नियमों के अनुसार केवल 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित सेवा में रखा जाता है, लेकिन अब नौसेना ने इस संख्या को 75 प्रतिशत तक और सेना व वायुसेना ने करीब 50 प्रतिशत तक बढ़ाने का सुझाव दिया है।

हालांकि इस पर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है और मामला सरकार और डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स के विचाराधीन है। सूत्रों के अनुसार, सेनाओं का मानना है कि आधुनिक हथियार प्रणालियों, नई तकनीकों और परिचालन अनुभव वाले प्रशिक्षित जवानों को अधिक समय तक सेवा में बनाए रखना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिहाज से लाभकारी होगा। हाल के सैन्य अभियानों और बदलते सुरक्षा परिदृश्य से भी यह महसूस किया गया है कि अनुभवी सैनिकों की संख्या बढ़ाना आवश्यक है।

रिपोर्टों के मुताबिक, यदि कुल 25 प्रतिशत की सीमा में तत्काल बदलाव नहीं भी होता है, तब भी विशेष और तकनीकी इकाइयों में अधिक संख्या में प्रशिक्षित अग्निवीरों को नियमित सेवा में शामिल करने जैसे विकल्पों पर विचार किया जा सकता है।

इसके अलावा भविष्य की भर्ती नीति और विभिन्न सैन्य इकाइयों की आवश्यकताओं के आधार पर अलग-अलग मॉडल भी अपनाए जा सकते हैं।

2022 में शुरू हुई थी अग्निपथ योजना

गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने 2022 में अग्निपथ योजना शुरू की थी। इसके तहत युवाओं की चार वर्ष के लिए सेना, नौसेना और वायुसेना में भर्ती की जाती है, जबकि सेवा अवधि पूरी होने पर चयनित 25 प्रतिशत अग्निवीरों को नियमित कैडर में शामिल करने का प्रावधान है। अब पहले बैच के कार्यकाल के समापन से पहले इस व्यवस्था की समीक्षा की जा रही है, जिससे प्रशिक्षित मानव संसाधन का बेहतर उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।

सिटीजन रिपोर्टर

अब आप भी बन सकते हैं समर एक्सप्रेस के सिटीजन रिपोर्टर। अपने इलाके की कोई भी समस्या, आयोजन, जानकारी या खबर हमें भेजें। आपके नाम के साथ प्रकाशित की जाएगी। अपनी खबर इस फोन नंबर 8699221114 या ईमेल infosummerexpress@gmail.com पर भेजें।

BOOK YOUR ADVERTISEMENT

If you want to publish your advertisement on our newspaper

समर एक्सप्रेस

CONTACT:
+91 6283 860 059

पेज 1 एंकर स्टोरी

एसजीपीसी और अकाली दल ने अभिव्यक्ति की आजादी पर उठाए सवाल

'सतलज' के हटने पर गरमाई सियासत, दिलजीत बोले- इंसानियत मर गई

समर न्यूज | चंडीगढ़

पंजाबी गायक एवं अभिनेता दिलजीत दोसांझ की बहुचर्चित फिल्म 'सतलज' को भारत में ओटीटी प्लेटफॉर्म जी5 से रिलीज के महज दो दिन बाद हटाए जाने के फैसले ने पंजाब में नया राजनीतिक और सामाजिक विवाद खड़ा कर दिया है। फिल्म मानवाधिकार कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा के जीवन और 1990 के दशक के पंजाब से जुड़े घटनाक्रम पर आधारित है।

फिल्म हटने के बाद दिलजीत दोसांझ ने सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि "इंसानियत मर गई" और यह भी कहा कि फिल्म के साथ वही हुआ जो खालड़ा के साथ हुआ था। साथ ही उन्होंने #आई चैलेंज द डार्कनेस हैशटैग का इस्तेमाल किया। फिल्म को लेकर विवाद उस समय और बढ़ गया जब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी (एसजीपीसी) और शिरोमणि अकाली दल भी खुलकर इसके समर्थन में सामने आए। एसजीपीसी ने कहा कि यह फिल्म पंजाब के इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय को सामने लाती है और युवाओं को इसे देखने का अवसर मिलना चाहिए।

समिति के पदाधिकारियों ने फिल्म को हटाए जाने को चिंताजनक बताते हुए इसे अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मुद्दा बताया। अकाली दल अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल का कहना है कि किसी ऐतिहासिक या सामाजिक विषय पर बनी फिल्म को इस तरह उपलब्ध न रहने देना अभिव्यक्ति की आजादी पर सवाल खड़े करता है।

हटाने का स्पष्ट कारण सार्वजनिक नहीं

इस पूरे घटनाक्रम के बीच जी5 ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा कि मौजूदा परिस्थितियों को देखते हुए 'सतलज' फिलहाल भारत में उपलब्ध नहीं रहेगी। हालांकि कंपनी ने फिल्म हटाने का स्पष्ट कारण सार्वजनिक नहीं किया। प्लेटफॉर्म ने यह भी कहा कि वह फिल्म को दोबारा दर्शकों तक पहुंचाने के लिए उपलब्ध कानूनी और नियामकीय विकल्पों पर काम कर रहा है तथा फिल्म के रचनात्मक दृष्टिकोण के साथ खड़ा है। निर्देशक हनी त्रेहान ने भी फिल्म हटाए जाने पर हैरानी जताई। उनके अनुसार उन्हें इस फैसले की जानकारी अचानक मिली और वे स्वयं भी इसके कारणों से अनभिज्ञ हैं। उन्होंने कहा कि फिल्म को लंबे संघर्ष के बाद उसके मूल स्वरूप में दर्शकों तक पहुंचाया गया था।

तीन साल बाद हुई थी रिलीज

यह फिल्म पहले 'पंजाब 95' शीर्षक से बनाई गई थी। केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के साथ लंबे समय तक चले विवाद, कथित तौर पर बड़ी संख्या में सुझाए गए संशोधनों और शीर्षक परिवर्तन के बाद इसे 'सतलज' नाम से ओटीटी पर रिलीज किया गया। थिएटर रिलीज के बजाय फिल्म को सीधे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया गया था। फिल्म हटाए जाने के बाद सोशल मीडिया पर भी बहस तेज हो गई है। बड़ी संख्या में लोगों ने इस फैसले पर सवाल उठाए।

सच दबा नहीं रह सकता: हरभजन

पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह ने भी फिल्म की सराहना करते हुए कहा कि सच हमेशा दबा नहीं रह सकता। फिलहाल फिल्म भारत में जी 5 से हट चुकी है, जबकि प्लेटफॉर्म ने भविष्य में इसे दोबारा उपलब्ध कराने के प्रयास जारी रखने की बात कही है। इस बीच, मामला केवल मनोरंजन जगत तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पंजाब की राजनीति, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और ऐतिहासिक विमर्श से जुड़े व्यापक मुद्दों पर भी चर्चा का केंद्र बन गया है।

चढ़ावा चोरी: चंपत राय का इस्तीफा मंजूर, कृष्ण मोहन नए महासचिव

एजेंसी | अयोध्या

राम मंदिर चढ़ावा चोरी के बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा का इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। चंपत राय की जगह नए ट्रस्टी रिटायर्ड IFS कृष्ण मोहन को कार्यवाहक महासचिव बनाया गया है।

चढ़ावा चोरी के बाद हुई पहली बैठक 3 घंटे तक चली। बैठक के बाद कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरी ने कहा कि चंपत राय ने कहा है कि जब तक अपराधी पकड़े नहीं जाते तब तक पद पर रहना सही नहीं है। जो हुआ वह कष्टदायी है। इससे हम सब दुखी हैं। चढ़ावा चोरी लज्जाजनक घटना है। बैठक में ट्रस्टी के. पाराशरन ने कहा था कि त्यागपत्र देते ही इसे स्वीकार करना ट्रस्ट के संविधान में हैं। इसलिए इस्तीफा स्वीकार किया गया। 22 जुलाई को ट्रस्ट की फिर बैठक होगी। कृष्ण मोहन ने कहा- चढ़ावा चोरी के आरोपियों को सजा दिलाएंगे। प्रबंधन की कमियों का फायदा उठाया गया, कमियों को दूर करेंगे। वहीं, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास ने कहा कि मुझे पीएम मोदी और सीएम योगी पर भरोसा है कि जो भी इस पाप से जुड़ा है, उसे कड़ी सजा दिलाएंगे।